फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 48 प्रभात जयपुर, शुक्रवार 18 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

MAKKAH AGREEMENT GEOMETRY RAISES...

Each of these countries faces diverse security challenges, for Saudi Arabia, it is presently Iran, while for Turkey, their issues are with Israel and Syria and for Pakistan, their focus is India

The Living Tradition of Hand Block Printing in Rajasthan

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रैज़ैंटेटिव ने ट्रंप को 100 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने का अधिकार दिया

भारत के समक्ष भारी दुविधा प्रस्तुत है, हाउस ऑफ रिप्रैज़ैंटेटिव द्वारा ट्रंप को दिए गए इस अधिकार से

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। अमेरिकी संसद के निचले सदन में एक बिल पास हुआ है, जो राष्ट्रपति को उन देशों पर 100 प्रतिशत तक नया टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, जो रुस से कच्चा तेल (क्रूड) आयात करते हैं। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति इस स्तर का नया टैरिफ लगाते हैं, तो यह भारतीय नीति-निर्माताओं के लिए बेहद कठिन फैसला हो सकता है।

अमेरिका भारत के सामने एक कठिन चुनौती रख रहा है, या तो अमेरिका का डटकर सामना करे और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखे या फिर अमेरिकी मांगों को स्वीकार करे और अपने ईंधन की अर्थव्यवस्था को संभालने में गंभीर समस्याओं का भी सामना करे, जिनमें घरेलू राजनीतिक मुद्दे भी शामिल हैं।

देश के सामने मौजूद इस ''हबसन्स चॉइस'' (दोनों तरफ से मुश्किल) की स्थिति को देखते हुए भारत के पास अमेरिका की दादागिरी का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

- **अगर, भारत इस धमकी के खिलाफ खड़ा होता है तो भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जा रहे 140 बिलियन डॉलर का व्यापार बंद होने की संभावना बनेगी। क्योंकि भारत का माल इस भाव में अमेरिका में बिक नहीं पाएगा।**
- **सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, भारत द्वारा रूस से खरीदे जा रहे ऑयल पर।**
- **अमेरिका, चीन को भी ऐसी धमकी देना चाहता है, पर, चीन ने अमेरिका को दुर्लभ ''रेअर अर्थ'' खनिजों की आपूर्ति पूरी तरह रोक देने की धमकी दी थी। रेअर अर्थ खनिज पर विश्व में चीन का एकाधिकार सा है, इसलिए अमेरिका की धमकी कामयाब नहीं हो पाई थी।**
- **अतः भारत के समक्ष पूर्ण दुविधा है, या तो चुपचाप अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त करे या हिम्मत दिखाए, अमेरिका को अंगूठा दिखाकर।**

एक ओर, इस स्तर का शुल्क लगाए जाने का मतलब यह हो सकता है कि भारत से निर्यात की जाने वाली ज्यादातर वस्तुओं के लिए अमेरिकी बाजार बंद हो जाए। किसी भी निर्यातक को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए टैरिफ की कीमत के आस-पास भी मार्जिन नहीं मिलता है। हालांकि भारत कई अन्य देशों की तरह निर्यात पर निर्भर देश नहीं है, लेकिन भारत से करीब 140 अरब डॉलर का निर्यात होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

दूसरी ओर, किन देशों से अपनी जरूरत की वस्तुएं आयात की जाए, इस चुनाव में अमेरिका के दबाव के आगे झुकना किसी भी देश के लिए एक बड़ी रणनीतिक हार होगी। भारत लगातार इस बात पर कायम रहा है कि उसे अपनी जरूरतों का आयात किस देश से करना है, इसका चुनाव करने की उसे स्वतंत्रता है।

अब तक, यूक्रेन युद्ध के संकट और ईरान युद्ध के दौरान पैदा हुए सबसे कठिन हालात के बावजूद भारत ईंधन की उस गंभीर कमी से बचा रहा है, जिसका सामना कई अन्य देशों को करना पड़ा। न तो तेल की आपूर्ति में भारी कमी आई और न ही खाना पकाने वाली गैस जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति खत्म हुई। दोनों की आपूर्ति काफी हद तक बनी रही।

ईंधन की आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट, खासकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति में, घरेलू राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। इससे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चंद्रशेखर टाटा संस के फिर कार्यकारी चेयरमैन बने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। टाटा संस के बोर्ड ने एन. चंद्रशेखरन को कार्यकारी चेयरमैन के रूप में पांच साल का नया कार्यकाल देने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला पिछले महीने उनके दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं करने के फैसले को पलटते हुए लिया गया है।

चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव के पक्ष में बोर्ड के सभी सदस्यों ने मतदान किया, सिवाय नोएल टाटा के, जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया।

- **उन्हें पाँच साल का नया कार्यकाल दिया गया है।**

इस मतदान से प्रस्ताव पर बोर्ड में मतभेद सामने आया है। नोएल टाटा ही ऐसे एकमात्र बोर्ड सदस्य रहे जिन्होंने चंद्रशेखरन को पद पर बनाए रखने का विरोध किया।

यह निर्णय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा टाटा संस द्वारा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में अपना पंजीकरण समाप्त करने के अनुरोध को खारिज किए जाने के कुछ ही दिनों बाद लिया गया है। इससे केन्द्रीय बैंक के नियमों के तहत टाटा संस के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना और बढ़ गई है।

चंद्रशेखरन का मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त हो रहा है। उनके फैसले में बदलाव के पीछे क्या

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी ऐसा क्या खाते हैं, जो 76 के होने पर भी पूरे फिट हैं

वे कोई भारी भरकम ''डॉयट चार्ट'' से नहीं बंधे हैं। मोदी के नज़दीकी लोगों का कहना है, उनका झुकाव परंपरागत भारतीय खान-पान की तरफ है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज 76 साल के हो गए हैं और उनकी फिटनेस दिनचर्या अक्सर लोगों की दिलचस्पी का विषय रही है। योग, व्यायाम और लंबे समय तक काम करना, उनकी सेहत से सम्बन्धित चर्चा का जाना-पहचाना हिस्सा है। लेकिन उनके खान-पान की आदतें काफी सरल और सामान्य हैं। ऐसा कोई विस्तृत डाइट चार्ट नहीं है जो उनके भोजन को तय करता हो, लेकिन पारंपरिक भारतीय भोजन, घर का बना खाना, स्थानीय सामग्री और समय-समय पर उपवास रखने के प्रति उनका झुकाव किसी से छिपा नहीं है।

मोदी के खान-पान से जुड़ी सबसे खास चीजों में से एक सहजन का पराठा है। सन् 2020 में पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर के साथ ''फिट इंडिया'' संवाद के दौरान उन्होंने बताया था कि वे सहजन की पत्तियों से पराठे बनाते हैं। सहजन को अंग्रेजी में ''ड्रमस्टिक लीव्स'' भी कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि ये पराठे वो सप्ताह में एक या दो बार खाते हैं। यह हरी पत्तेदार सब्जी को रोजमर्रा के भारतीय भोजन में शामिल करने का एक आसान तरीका है। सहजन में फाइबर, विटामिन और खनिज सहित, कई अन्य पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं।

- **उन्हें सबसे ज्यादा पसंद मोरिंगा पराठा है, जो ड्रमस्टिक के पत्तों से बनता है।**

उनके रोजमर्रा के भोजन सम्बन्धी विचार भारतीय घरों में बनने वाले सामान्य भोजन पर आधारित हैं। सन् 2020 के फिट इंडिया संवाद में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पोहा और उपमा के साथ-साथ, अलग-अलग क्षेत्रों के व्यंजनों का भी जिक्र हुआ था। इसका मुख्य संदेश ताजा बना हुआ खाना खाने, और पैकेज्ड तथा प्रोसैस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने का था। यही वजह है कि वे दाल-चावल और घी का भी जिक्र करते रहे हैं, किन्तु वे इन्हें किसी नए चलन वाले स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में नहीं, बल्कि पारंपरिक भारतीय भोजन के सामान्य हिस्से के रूप में देखते हैं।

उपवास उनकी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा है!

उनके उपवास के नियम काफी सख्त हैं। 2025 में लैक्स फ्रिडमैन के साथ हुई बातचीत में, मोदी ने चातुर्मास और नवरात्रि के दौरान किये जाने वाले अपने उपवास के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि चातुर्मास के दौरान, जो उनके लिए लगभग जून के मध्य से दिवाली के बाद तक चलता है, वे 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करने की दिनचर्या का पालन करते हैं।

उन्होंने कहा था कि सितंबर या अक्टूबर में आने वाली नवरात्रि के दौरान, वे नौ दिनों तक बिल्कुल भोजन नहीं करते और केवल गर्म पानी पीते हैं।

चैत्र नवरात्रि के दौरान उनकी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मणिहारों के कटले की आग 25 दुकानों में फैली

तीन मंजिला सेठी कॉम्पलेक्स में चूड़ी, कपड़े, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक के कारण आग तेजी से फैली

जयपुर, 17 सितम्बर। माणक चौक थाना क्षेत्र स्थित त्रिपोलिया बाजार के मणिहारों के कटला (पुरोहितजी का कटला) में गुरुवार सुबह करीब 7 से 7:30 बजे के बीच तीन मंजिला सेठी कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल स्थित दुकानों और गोदामों तक फैल गई। चूड़ी, मणिहारी सामान, कपड़े, रेडीमेड आइटम, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक, खिलौने और ज्वेलरी सहित, बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामान होने से आग तेजी से फैलती गई। करीब 25 दुकानें आग की चपेट में आने की जानकारी सामने आई है, जबकि करीब 15 से 20 दुकानों में भारी नुकसान बताया जा रहा है।

आग बुझाने के लिए जयपुर के विभिन्न फायर स्टेशनों से 25 से 30 दमकल वाहन मौके पर भेजे गए। 20 से अधिक सिविल डिफेंस कर्मचारी भी राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। संकरी गलियों के कारण दमकल वाहन कॉम्प्लेक्स तक सीधे नहीं पहुंच सके। ऐसे में मुख्य सड़क पर खड़ी दमकलों से सैकड़ों मीटर लंबे पाइप गलियों के भीतर ले जाकर पानी की बौछार की गई। निजी पानी टैंकरों से भी पानी मंगवाया गया। दोपहर तक करीब 18 दुकानों की आग पर काबू पाने की जानकारी दी गई, लेकिन कई दुकानों से धुआं उठता रहा और दमकलकर्मी कूलिंग का काम करते रहे।

- **संकरी गलियों के कारण दमकल कॉम्पलैक्स तक नहीं पहुँच सकी। मुख्य सड़क से सैंकड़ों मीटर लंबे पाइप से आग बुझाने के लिए पानी की बौछार की गई।**
- **स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, कॉम्पलैक्स की ऊपरी मंजिल पर रेस्टोरैंट और होटल का निर्माण कराया जा रहा था, वहाँ सुबह वैल्डिंग का काम होता था। व्यापारियों को आशंका है कि वैल्डिंग की चिंगारी से आग लगी हो सकती है।**

हादसे के समय बाजार बंद था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चौकीदार विक्रम सिंह ने दुकानों से धुआं उठता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तत्कालीन कलैक्टर को वारंट के बाद भी पेश नहीं करने पर जालौर एसपी तलब

जालोर, 17 सितम्बर (कासं)। जिला उपभोक्ता आयोग जालोर के पीठासीन अधिकारी धनश्याम यादव ने बेटियों की शादी के लिए एक श्रमिक महिला को निर्धारित सहायता राशि नहीं मिलने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन जालोर कलेक्टर एवं वर्तमान श्रम आयुक्त पूजा पार्थ के खिलाफ वारंट जारी किया था। लेकिन गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद भी आज तक उसकी पालना नही करने पर आयोग के अध्यक्ष यादव ने जालोर एसपी शैलेन्द्रसिंह इन्दोलिया को तलब किया गया।

- **जिला उपभोक्ता आयोग ने जालौर एसपी शैलेन्द्र सिंह को 22 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'दलबदल विरोधी कानून के मौजूदा ढांचे को पूर्णतया बदलना आवश्यक'

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का कहना है कि वर्तमान कानून को हटाकर केवल एक सरल प्रावधान लागू होना चाहिए, जिसके तहत किसी भी सांसद या विधायक को मध्यावधि में दलबदल करने के लिए 10 वर्ष तक अपात्र घोषित कर दिया जाए

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। वरिष्ठ अधिवक्ता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची में पूरी तरह बदलाव की मांग किए जाने के बाद, दलबदल विरोधी कानून पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है।

हाल ही में कोच्चि में बोलते हुए सिब्बल ने मौजूदा व्यवस्था को खत्म करने और उसकी जगह एक सरल प्रावधान लाने का सुझाव दिया। इसके तहत, कार्यकाल के बीच में पार्टी बदलने वाले किसी भी सांसद या विधायक को 10 साल तक सार्वजनिक पद या किसी संवैधानिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा विलय संबंधी अपवाद एक ऐसी खामी बन गया है, जो वास्तविक पार्टी पुनर्गठन के बजाय, बड़े पैमाने पर दलबदल को बढ़ावा देता है। उनका तर्क था कि न तो इस्तीफा देने और न ही दूसरी पार्टी में विलय करने से दलबदल करने वालों को सजा से छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, ''जो भी व्यक्ति कार्यकाल के बीच में अपनी पार्टी बदलेगा, वह अगले 10 साल तक सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकेगा... इसके बाद कोई भी दलबदल नहीं करेगा।''

- **सिब्बल का कहना है कि वर्तमान कानून में दो तिहाई सांसद या विधायकों के विलय करने का अपवाद एक ऐसी खामी बन गया है जो वास्तविक पार्टी पुनर्गठन के बजाय बड़े पैमाने पर दलबदल को बढ़ावा देता है।**
- **सिब्बल ने कहा कि विलय करने का प्रावधान किसी पार्टी में वास्तविक और जमीनी बदलाव को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है।**
- **सिब्बल ने हाल ही में हुए कुछ उदाहरण उद्धृत किए जैसे कि इस प्रावधान का दुरूपयोग करके ही टीएमसी के 20 सांसदों का ''नैशनलिस्ट सिटीजन पार्टी'' में विलय किया गया ताकि वे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को समर्थन दे सकें।**

ये बयान ऐसे समय आए हैं, जब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'एसटी आरक्षण में से 9 प्रतिशत भील समुदाय को क्यों नहीं दिया जाए'

जयपुर, 17 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव, एसटी आयोग और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि एसटी वर्ग को दिए जा रहे 12 फीसदी आरक्षण में से 9 फीसदी आरक्षण भील समुदाय को क्यों ना दिया जाए। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने ये आदेश शंकर लाल दहिया व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

- **हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव, एसटी आयोग व केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किए।**

याचिका में अधिवक्ता मनोज चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ''आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति'' के सदस्य हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यू.एस. फैडरल रिज़र्व द्वारा ''इंटरैस्ट रेट'' बढ़ाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा

रेट बढ़ने से डॉलर मजबूत होगा और भारतीय रूपया कमज़ोर होगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। अमेरिकी फैडरल रिज़र्व द्वारा हाल में ब्याज दर बढ़ाए जाने का भारत पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसका मतलब है कि डॉलर और मजबूत हो सकता है, रुपये पर दबाव बढ़ सकता है, ग्लोबल फाइनैंशियल हालात कड़े हो सकते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए स्वतंत्र रूप से ब्याज दरों में कटौती करने की गुंजाइश कम हो सकती है। इसलिए ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल अमेरिकी मौद्रिक नीति में बदलाव नहीं है। इसका असर भारतीय बॉन्ड की ब्याज दरों, विदेशी पूंजी के प्रवाह, शेयर बाजार, आयात से जुड़ी महंगाई और भारतीय कंपनियों के लिए कर्ज लेने की लागत पर भी पड़ सकता है।

फैडरल रिज़र्व द्वारा अपनी प्रमुख फैडरल फंड्स ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट, यानी 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि कर्ज लेने की लागत की तुलना में महंगाई उसकी बड़ी चिंता का विषय है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फैडरल रिज़र्व ने संकेत दिया है कि इस साल बाद में एक और बढ़ोतरी हो सकती है। चेयरमैन केविन वार्श का यह कहना कि सैंट्रल बैंक ने ''आसान नीति की एक डोज़ हटा दी है'' (रिमूण्ड अ डोज़ ऑफ एकॉमोडेशन), असल में यह बताता है कि पैसे और कर्ज की लागत बढ़ाकर मौद्रिक नीति को और सख्त किया जा रहा है। कीमतों में स्थिरता हासिल करने के लिए फैड गंभीर है, यह आश्वासन बताता है कि वह महंगाई को अपने तय लक्ष्य तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

- **फैडरल रिज़र्व बैंक के 25 ''बेस पाइंट'' से रेट बढ़ाने के फैसले से निवेशकों के लिए अमेरिका में निवेश करना ज्यादा आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक मजबूत डॉलर की वजह से निवेश की गई राशि पर बेहतर ''रिटर्न'' मिलेगा। वहीं भारत जैसे ''एमर्जिंग मार्केट'' निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाएंगे।**
- **डॉलर के मजबूत होने की वजह से भारतीयों के लिए विदेश से आयात करना और भी महंगा हो जाएगा जिससे घरेलू महंगाई भी बढ़ सकती है।**
- **फैडरल के रेट बढ़ाने के फैसले से उत्पन्न हुए कड़े वित्तीय हालात आर.बी.आई. के लिए भारत की घरेलू व्यवस्था को संभालने के लिए उपलब्ध विकल्प भी कम कर देगा। वहीं, भारतीय कंपनियों के लिए भी विदेशी ''फायनैंसिंग'' या लोन लेना और भी महंगा हो जाएगा।**

भारत के लिए इसका सबसे तत्काल असर रुपये पर पड़ता है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर आधारित एसैट्स, खासकर अमेरिकी सरकारी सिक्यूरिटीज़, निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो जाती हैं। अगर ग्लोबल निवेशक अपनी कुछ पूंजी अमेरिका की ओर ले जाते हैं, तो रुपये सहित, उभरते बाजारों की करैंसी पर गिरावट का दबाव पड़ सकता है। रुपये के कमज़ोर होने से आयात महंगा हो जाता है और इससे घरेलू महंगाई बढ़ सकती है।

इस घटनाक्रम से रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले भी मुश्किल हो जाते हैं। अगर अमेरिका लगातार ब्याज दरें बढ़ाता है, जबकि भारत कम ब्याज दरों के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहता है, तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच ब्याज दरों के बीच का अंतर कम हो जाएगा। इससे निवेशक अपनी पूंजी डॉलर एसैट्स (परिसंपत्तियों) की ओर ले जा सकते है और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि भारतीय रिजर्व बैंक को फेड की तरह ब्याज दर बढ़ानी पड़ें, क्योंकि भारत की मौद्रिक नीति मुख्य रूप से घरेलू महंगाई और आर्थिक विकास की स्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन फेड की सख्त नीति से रिज़र्व बैंक के पास फैसले लेने की गुंजाइश जरूर कम हो जाएगी।

भारतीय सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर भी ऊपर की ओर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरें वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो जाती हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुतिन ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी

नई दिल्ली, 17 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो काउसीनो ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। तीनों संदेशों में भारत के साथ अपने-अपने देशों के संबंधों को मजबूत करने में मोदी की भूमिका का उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पुरानी मुलाकात की तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशवासियों का गहरा सम्मान और वैश्विक मंच पर व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त है। भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मोदी के व्यक्तिगत योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता।

- **उन्होंने कहा कि मोदी को वैश्विक मंच पर व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त है।**